भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1828

दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आपदा से बचाव के उपाय

1828. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है कि जल जीवन मिशन की जलापूर्ति योजनाएं कोडागु में हाल ही में हुई बाढ़ की घटनाओं के अनुरूप हों, और
- (ख) क्या जल अवसंरचना के लिए आपदा रोधी उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। अतः ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु व्यक्तिगत परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, कोडागु जिले में जल जीवन मिशन के तहत सूचित किए गए भूजल स्तर और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर कई "एकल ग्राम योजनाएं" (गांव अवस्थित निर्माण कार्य) हैं।

इन एकल ग्राम योजनाओं (गांव अवस्थित निर्माण कार्य) के तहत संस्थापित प्रेशर फिल्टर और निर्मित अन्य लघु बुनियादी ढांचे को संरचनाओं की पर्याप्त सुरक्षा को सक्षम बनाने और बाढ़ जैसी आपदाओं से सुरक्षित बनाने के लिए "मानक कोड" पर विचार किया जाता है।

(ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यसंबंधी दिशानिर्देश के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से जल बुनियादी ढांचे की रक्षा के साथ-साथ कोडागु जैसे क्षेत्रों में बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है:

- i.) **अवसंरचना आयोजना:** बाढ़-प्रवण, भूस्खलन-प्रवण और भूकंपीय क्षेत्रों से बचने के लिए शोधन संयंत्रों, जलाशयों और पाइपलाइनों जैसी जल आपूर्ति अवसंरचना हेतु स्थानों का चयन। बाढ़ या कीचड़ के बहाव के दौरान पाइपलाइनों को बहाव के साथ बहने से रोकने के लिए इनकी सुरक्षित रूप से संस्थापना।

- ii.) **सुरक्षा मानकों का अनुपालन:** यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और केंद्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाए।
- iii.) **सामुदायिक भागीदारी:** आपदा योजना में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और सुभेद्यताओं को अभिचिह्नित करने तथा अवसंरचना हेतु स्थल चयन को अनुकूलित करने के लिए उनके ज्ञान का उपयोग करना।
- iv.) **आपदा तैयारी:** अभिचिह्नित टिकाऊ जल स्रोतों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र वाली आकस्मिक आयोजनाएं तैयार करना, जिनमें मोबाइल जल शोधन संयंत्र और आपातकालीन जल आपूर्ति किट शामिल हों।
- v.) **आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय:** आपदाओं के दौरान पूर्वनिर्धारित आपातकालीन जल आपूर्ति किट नियोजित करना और मोबाइल जल शोधन इकाइयाँ स्थापित करना। जलजनित रोगों की निगरानी और रोकथाम के लिए जल गुणवत्ता निगरानी का संचालन करना।
- vi.) **आपदा के बाद पुनर्निर्माण:** भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए, "बेहतर निर्माण करें" सिद्धांतों पर ध्यान देकर क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति प्रणालियों की बहाली को प्राथमिकता देना।
- vii.) **जेजेएम निधि का उपयोग:** राज्य जेजेएम के वार्षिक आवंटन का 25% फ्लेक्सी फंड के रूप में उपयोग कर सकता है और प्राकृतिक आपदा के बाद तत्काल बहाली के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) का भी उपयोग कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्राकृतिक आपदाओं/विपतियों और आंतरिक गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों/मुद्दों से निपटने के लिए जेजेएम के तहत वार्षिक आवंटन का कम से कम 5% अलग रखें और यदि वित्तीय वर्ष के अंत में यह अप्रयुक्त रहता है तो उस वित्त वर्ष के अंत में कवरेज के लिए उसका उपयोग राज्य द्वारा किया जा सकता है।
- viii.) **आपदा उपायों का एकीकरण:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 खंड 2 (ख) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है कि आपदा शमन उपायों को परियोजना डिजाइनों में शामिल किया गया हो और सभी नए जल अवसंरचना विकासों में आपदा प्रबंधन एक मूलभूत भाग हो।

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत कोडागु जिले में कोई बहु-ग्राम-योजनाएं (एमवीएस) स्थापित नहीं की गई हैं, जिनमें आम तौर पर जैकवेल, एरेटर, क्लैरिफ्लोक्यूलेटर, फिल्टर बेड, क्लोरीनीकरण यूनिट, अवसादन टैंक आदि जैसी प्रमुख संरचनाएं शामिल होती हैं और जो आम तौर पर आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। प्रस्तावित योजनाएं भूजल पर आधारित हैं, जिसमें गांव में पाइप लाइन नेटवर्क शामिल हैं, जो मिट्टी के स्तर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रतिरोधी हैं।